भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2067

उत्तर देने की तारीख : 14.12.2023

एमएसएमई को अग्रिम राशि के भुगतान से छूट

2067. श्री राजेश नारणभाई चुडासमा :

श्रीमती पूनम महाजन :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) इकाइयों और एमएसएमई के यप में पंजीकृत नए स्टार्ट-अप को क्या लाभ दिए जा रहे हैं;

(ख) क्या एमएसएमई इकाइयों को सरकारी निविदाओं के लिए अग्रिम राशि भुगतान (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट-ईएमडी) के भुगतान से छूट दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या एमएसएमई कइायों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि छूट के अनुदेशों के बावजूद उनहें सरकारी निविदाओं में ईएमडी का भुगतान करने के लिए कहा जा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा आौर इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) अनुदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच), एमएसएमई चैंपियंस आदि योजनाएं शामिल हैं।

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 भी अधिसूचित किया गया है। इस नीति में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा 25% वार्षिक खरीद एमएसई से करना अनिवार्य किया गया है, जिसमें 4 प्रतिशत खरीद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केउद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से और 3 प्रतिशत खरीद महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से किया जाना शामिल है।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी हां, दिनांक 23 मार्च, 2012 की राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 581(अ) के माध्यम से अधिसूचित एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 में सरकारी निविदाओं के लिए धरोहर राशि के भुगतान (ईएमडी) से छूट के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(घ) से (ङ) नीति के गैर-अनुपालन से संबंधित, एमएसई की शिकायतों के निवारण के लिए एमएसएमई मंत्रालय में "चैंपियंस पोर्टल" नामक एक शिकायत कक्ष स्थापित किया गया है।

****